SHRI NAGEN SAIKIA: I wish to draw the attention of the Government and the House that such practices should be immediately stopped at any cost so that the morale of the country is not destroyed in this way. (*Time bell Rings*) All right, I conclude.

Need for speedy implementation of Upper Sakri Reservoir Project in South Bihar

श्री सूरज प्रसाद (बिहार) : महोदय, मैं बिहार मे एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना अपर सकरी जलाशय परियोजना की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। बिहार का उत्तरी भाग बाढ से और दक्षिणी भाग सूखे से करीब हर साल पीडित रहता है। ऐसी हालत में दक्षिणी बिहार को सूखे से मुक्त कराने के लिए सिंचाई साधनों का विकसित करना जरूरी है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिवंगत श्री चन्द्रशेखर सिंह, मुख्य मंत्री बिहार सरकार ने अपर सकरी जलाशय परियोजना का शिलान्यास 20 अक्तूबर, 1984 को किया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यह योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल नही की गयी। अगर यह योजना लागू कर दी गई तो नवादा नालदा और मुंगेर जिले का बड़ा भाग सिंचित होने लगेगा और इस क्षेत्र को सूखे से मुक्त किया जा सकेगा। इससे अन्न के मामले में भी बिहार को आत्मनिर्भर होने में मदद मिलेगी। इस योजना को लागू करने के लिए इस क्षेत्र के किसान संघर्ष के पथ पर आरूढ़ है, वे जिला कलेक्टर के सामने प्रदर्शन कर चुके हैं और 10 दिसम्बर, 1987 को हजारो की संख्या मे इस क्षेत्र के किसानों ने बोट-क्लब के सामने धरना देकर प्रधान मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। . . . **(समय की घंटी)** . . .

महोदय, यह एक मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास के बाद भी इस योजना को लागू न करना हास्यास्पद है और उनके पद और प्रतिष्ठा का मखौल है। अत: मै मांग करता हूं कि अपर सकरी जलाशय परियोजना को लागू करने और समुचित साधन इसके लिए मुहैय्या कराने के लिए जरूर कदम उठाए जायें ताकि यह योजना शीघ्र लागू की जा सके।

Attempt to scuttle CBI investigation into the serious offences committed by Coal Industry Officials.

SHRI SUIL BASU RAY (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, I want to draw the attention of the Government to a sordid affair happening in Bihar in the coalfields. The Statesman has come out with a news item on 10-12-1987 in headlined: "CBI's Wings clipped" and it says·

> "When the Bihar Government recently wrote to the Centre expressing its intention to get back the services of the Superintendent of Police, CBI here, it was apparent that the move was a sequel to the pressure of coal lobby over the State Government. This action of the Bihar Government was taken in the face of fourteen officials who had to face CBI searches. In all twentysix premises were raided."

We know coal is black; but we do not know how much blacker the administration is. In the face of this action of the Government, ultimately the CBI Directorate at Delhi has succumbed to the pressure of Bihar Government and the coal lobby and the mafias and there is going to be no action taken against these blackmarketeers. So I demand that necessary inquiry should be made and appropriate action taken. I also demand a statement from the Energy Minister on the floor of this House.

Shortage of Drinking Water in Rajasthan

श्री भवर लाल पंवार : (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे साथी, श्री संतोष बागडोदिया, जोकि राजस्थान के ही है, उनका समय भी आपसे मागूगा। महोदय, शताब्दी के भीषण अकाल के इस वर्ष मे राजस्थान एव विशेषकर पश्चिमी राजस्थान अत्यधिक प्रभावित हुआ है और इसके जोधपुर, क्षेत्र को पेयजल समस्या अत्यधिक गंभीर हो गई है।

[श्री भंवर लाल पवार]

जोधपुर की आबादी कुछ ही वर्षों मे दुगुनी होकर लगभग 8 लाख हो चुकी है जिसमें मिलिट्री की सख्या लगभग 2 लाख हैं। इस जोधपुर क्षेत्र की पेयजल की आवश्यकता लगभग 125 लाख गैलन प्रतिदिन की है और इस आवश्यकता की सम्पूर्ण पूर्ति काफी समय से लगातार लगभग 4 वर्षों से अनावृष्टि एवं अकाल के कारण नहीं हो पा रही है।

जोधपुर की पेयजल की पूर्ति का बडा हिस्सा जवाई बाध के द्वारा होता रहा है। जवाई बाध में भी वर्षा के अभाव मे पानी का लेवल शनै शनै: कम होने के कारण एवं उसका पानी सिचाई के लिए भी उपलब्ध करा देने के फलस्वरूप जोधपुर की पेयजल योजना के अत्यधिक चरमरा गई है और इसके कारण जोधपुर के पास के इलाके रामपुरा से नलकूपों के माध्यम मे पाइप के द्वारा पीने के लिए पानी जोधपुर लाना पड़ा और वह पानी भी मीठा नही परन्तु कड़वा है।

जवाई बांध मे इस वर्ष अनावृष्टि के फलस्वरूप पानी का भराव नहीं हुआ और डेड स्टोरेज का पानी भी लिफ्ट करके जोधपुर निवासियो को पीने के लिए देना पडा और वह डेड स्टोरेज का पानी भी 30 नवम्बर 1987 को लगभग समाप्त हो गया।

दैनिक 125 लाख गैलन पानी की आवश्यकता को घटाकर 90 लाख गैलन करनी पड़ी और पानी की यह सप्लाई भी प्रतिदिन न कर एक दिन छोडकर दूसरे दिन करनी पड़ी और ऐसा समय आ गया है कि अब 3 दिन में भी एक बार पानी देने की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

जोधपुर की पेयजल समस्या गम्भीर नही हो जाए इसके लिए गत वर्ष राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया था कि जवाई बाध से सिचाई के लिए पानी नहीं लिया जाए परन्तु इसके उपरान्त भी राज्य सरकार के निर्णय की अवहेलना करते हुए अधिकारीगण एवं सम्बन्धित मंत्री के द्वारा पूर्ण नियंत्रण नहीं रखने के फलस्वरूप लगभग 2 हजार एम सी एफ टी पानी सिंचाई के लिए दे दिया गया। यदि यह पानी गत वर्ष सिंचाई के लिए नहीं दिया जाता तो इस वर्ष इस भीषण अकाल के समय पूरे साल भर जोधपुर को आसानी से पानी उपलब्ध हो जाता परन्तु राज्य सरकार के अदूरदर्शिता के कारण इस साल जोधपुर की पेयजल की समस्या बहुत गम्भीर हो गई है और सर्वत्र भय एवं आतंक व्याप्त हो चुका है।

जल वितरण के सबंध मे राजस्थान सरकार ने केबिनट स्तर के लिए गए निर्णय को अनदेखी करने के फलस्वरूप सरकार को करोडों रुपए का विशेष खर्च करने पर इस वर्ष बाध्य होना पड़ा है अन्यथा यह करोड़ों रुपया प्रदेश के विकास मे लग सकता था। जोधपुर क्षेत्र की पेयजल की समस्या को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने राजस्थान के हाल के दौरे के समय स्वयं ने देखा और समस्या के प्रति गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए शीघ्र ही युद्ध स्तर पर कार्य कर पेयजल समस्या के निवारण के निर्देश दिए और विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की। चूंकि जवाई बाध से जोधपुर क्षेत्र के लिए पीने के पानी का स्रोत अवरुद्ध हो गया इसलिए जोधपुर क्षेत्र के आस पास रामपुरा, मनई, रणसी गाव, बीजवाड़िया, पीपर, पाचला, बालरवा इत्यादि गांवो में लगभग 40 नलकूपों के द्वारा पेयजल व्यवस्था का कार्यक्रम लगभग 20 करोड की लागत का बनाना पड़ा। इन नलकूपों के द्वारा वे केवल 50 से 60 लाख गैलन तक भी पानी उपलब्ध होने की आशा है और इसके अलावा पीपाड़ क्षेत्र से रेल के माध्यम से पानी पहुंचाने के लिए भी लगभग 16 करोड़ की योजना हाथ में ली गई है। इस वैकल्पिक योजना का पूरा होना भी इस बात पर निर्भर करता है कि आने वाले समय मे भूमिगत जल का स्तर रह पाएगा या नहीं।

लगातार 4 वर्षो के अकाल के कारणवश राजस्थान मे भूमिगत जल का स्तर 100 फुट से लगाकर लगभग 400 फुट की सतह तक गहरा चला गया है ऐसी

सभा में वर्तमान मे वैकल्पिक पेयजल योजना के लिए खोदे जाने वाले नलकूपो से अगली जून-जुलाई तक पानी उपलब्ध हो पायेगा या नही यह भी एक चिन्ता का विषय है।

पश्चिमी राजस्थान की और विशेषकर जोधपुर सम्भाग की पेयजल समस्या के निवारण के लिए प्रधान मंत्री जी ने 1983 मे जोधपुर में आम सभा में घोषणा की थी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पीने के पानी की समुचित व्यवस्था जोधपुर के लिए शीघ्र ही कर दी जायेगी। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इंदिरा गांधी परियोजना के संबध में केन्द्र सरकार की ओर से मार्च, 1986 तक 40 करोड 1986-87 मे 5 करोड़ 1987-88 में 5 करोड़ लगभग एडवांस प्लांट असिस्टेन्ट्स राजस्थान को उपलब्ध कराया गया।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पूरे करने का लक्ष्य भारत के निर्माणकर्त्ता प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू जी के मन में थी जिसका शिलान्यास मार्च 1958 मे किया गया और केवल 66.46 करोड़ की लागत से 1968-69 में परियोजना सम्पूर्ण करने का था। बड़ा खेद का विषय है कि यह परियोजना द्रोपदी का चीर बन गई और पिछले तीन दशक में भी पूरी नही हो जाने के कारण इसकी लागत समय-समय पर बढ़ती हुई अब दो हजार करोड के लगभग पहुंच गई है।

राजस्थान की आर्थिक हालत बहुत कमजोर होने के कारण राज्य सरकार सन् 1958-68 के दशक में प्रति वर्ष केवल 5 करोड़ एव 68 से 78 के दशक में प्रति वर्ष केवल 15 करोड और 1978 से 83 की अवधि में प्रति वर्ष केवल 30 करोड सालाना ही इस परियोजना पर व्यय कर पाई है और इस गति को देखते हुए राज्य सरकार आने वाले हुई दशकों तक इस परियोजना को पूरा नही कर पायेगी। इसलिए राज्य सरकार की ओर से वर्ल्ड बैंक से 800 करोड़ के ऋण की मांग की गई है। यह परियोजना एसा लगता है राज्य सरकार के नियंत्रण के बाहर है जो कि इस परियोजना के पिछले 30 साल की अवधि मे बढती हुई अनियमतताएं एवं भ्रष्टाचार जिसकी पुष्टि रामसिंह कमीशन रिपोर्ट से हुई है से होती है। यद्यपि राज्य सरकार भी इस परियोजना को केन्द्र के द्वारा पूरा कराने का पूर्व मे अनुरोध किया था जिसे केन्द्र ने अस्वीकार कर दिया था किन्तु वर्तमान की परिवर्तित स्थिति को देखते हुए और पश्चिमी राजस्थान विशेष जोधपुर सम्भाग की पेयजल समस्या का शीघ्र निवारण के लिए एव मुख्य नहर के मदासर ग्राम से लेकर बाप तक के 40 किलोमीटर, बाप से फलौदी तक के 30 किलोमीटर एवं फलौदी से जोधपुर तक के 130 किलोमीटर तक पानी जोधपुर तक लाने के लिए परियोजना का यह हिस्सा केन्द्र सरकार अविलम्ब अपने हाथ में लेने की नितान्त आवश्यकता है।

आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार एवं प्रधान मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि—

1—केन्द्र से अविलम्ब हाई पावर टेक्नीकल टीम भेज कर परियोजना के इस कार्य का संचालन कराया जावे। चाहे राज्य सरकार को इसके लिए सुपरविजन चार्जेज भी देना पड़े।

2—पीने के पानी की योजना को प्राथमिकता देते हुए इस कार्य का संचालन कास्ट शेयरिंग बेसस पर डिफेंस को सुपुर्द किया जावे।

3—मैट्रोलोजीकल विभाग के द्वारा जाँच कराई जावे कि पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए खोदे गये एवं खुदने वाले नलकूपों में पानी की मात्रा इतनी है। अन्यथा पानी के समाप्त होने पर करोड़ों की लागत बेकार हो जायेगी।

4—वर्ल्ड बैंक से राज्य सरकार द्वारा मांगी गई 800 करोड़ की ऋण राशि स्वीकृत होने तक इसके लिए केन्द्र सरकार राशि का प्रावधान कर योजना पूरी कराये जाये।

[श्री भंवर लाल पवार]

यदि यह पेयजल सम्बन्धी परियोजना फरवरी 1988 तक पूरी नही की गई तो पश्चिमी राजस्थान एवं जोधपुर सम्भाग त्राहि-त्राहि मचाने लग जायेगा। जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जायेगा एव पशुधन पानी और चारा के अभाव में नष्ट हो जायेगा।

Compulsory Study of English, Replacing Hindi, in Middle Schools in Gujarat.

डा० बापू कालदाते (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय मैं एक अत्यन्त गंभीर और चिन्ताजनक विषय की ओर आप का ध्यान इस लिए खींच रहा हूं कि गुजरात में जिस ढंग से एन०सी०ई०आर०टी० की तरफ से माध्यमिक शिक्षा मे अंग्रेजी को थोपने का प्रयास किया जा रहा है उस के संबंध में मैं आप के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं। आप स्वयं जानते हैं कि गुजरात विद्यापीठ गांधी जी और सरदार पटेल जी की प्रेरणा से शुरू हुई थी जहां से रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं की शिक्षा का प्रबंध किया जाता है। मैं ज्यादा डिटेल में न जाते हुए गुजरात विद्यापीठ के वाइस चांसलर का जो पत्र है उस में से कुछ अंश आप को पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। उस से ही मेरा कथन समाप्त हो जायगा। वह इस प्रकार है :—

"गुजरात में 1960 से माध्यमिक शिक्षण के स्तर पर श्रेणी 8 9 10 में मातृभाषा हिन्दी और राष्ट्र भाषा पढ़ायी जाता है। 1960 से सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट की एस०एस०सी० सार्वजनिक परीक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रश्नपत्र वैकल्पिक है। पिछले साल 92000 विद्यार्थी मातृभाषा और हिन्दी के विषय के साथ उत्तीर्ण हु । श्रेणी 10 के अन्त मे सार्वजनिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो कर यह सब अपने अपने गांवों मे प्राथमिक शिक्षण ग्राम सेवक सहकारी कार्यकर विस्तरण कार्यकर जैसी जगहों में भर्ती हो कर अपनी आर्थिक स्वनिर्भरता सिद्ध कर रहे हैं। 27 साल से यह सिलसिला चला आता है। गुजरात में श्रेणी पांचवीं से हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। अब भारत सरकार की संस्था एन०सी०ई० आर०टी० के दबाव से गुजरात के माध्यमिक शिक्षण बोर्ड ने अंग्रेजी विषय लेना फरजियात (अनिवार्य) कर दिया है। इस से गुजरात में जो 92000 विद्यार्थी अब तक अंग्रेजी विषय को छोड़ कर भी स सफल होते रहे यह सब ग्रामवासी और गरीब विद्यार्थियों को इस सहुलियत से वंचित करना बड़ा अन्याय है। स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी भाषा ले कर ही सार्वजनिक परीक्षा मे उत्तीर्ण होना अनिवार्य करना यह एक बड़ी जबरदस्ती है। स्वराज्य प्राप्ति के 40 वर्ष के बाद भी अंग्रेजी फरजियात करना असंगत बात है और जब पिछले 27 सालों से गुजरात मे यह सिलसिला चला आ रहा है तो नई शिक्षण नीति के नाम इस का स्वागत करने के बजाय लाखों विद्यार्थियो को जो सहुलियत मिली हुई है उस को छीन लेना यह गलत बात है। विशेषतः यही विद्यार्थी अंग्रेजी के विकल्प में पिछले 27 साल से सिलाई कताई बुनाई, चित्रकला, संगीत, टाइपिंग जैसे व्यावसायी विषय लेते रहे हैं। यह सुविधा भी बंद करने का प्रस्ताव है। नई शिक्षण नीति ने साफ कहा है कि माध्यमिक शिक्षण की आठवी कक्षा से भी व्यावसायी विषय दाखिल हो सकते हैं। फिर भी गुजरात मे इस से विपरीत हो रहा है।"

यह उन्होंने कहा है। मैं सिर्फ आप के माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं कि राष्ट्र भाषा की सरकार की नीति के खिलाफ यह नीति न और हिन्दी भाषी लोगों पर अंग्रेजी ठूसने का यह जो प्रयास है इस को माननीय शिक्षा मंत्री जी देखें और इस को दुरुस्त करने का तुरन्त प्रयास करें।

Need for Statehood for Delhi

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : आप के द्वारा और सदन के माध्यम से मैं दिल्ली में विधान सभा तुरन्त बनाये जाने की मांग कर रहा हूं। साथ ही दिल्ली को प्रथम श्रेणी का राज्य घोषित करने की मांग कर रहा हूं अपने गृह मंत्री, भारत सरकार से।